IJGMRA | ISSN (online): 3107-6483
April-June 2026 | Vol. 2 | Issue 1

21वीं सदी में बहुध्रुवीयता और वैश्विक व्यवस्था का पुनर्गठन: चुनौतियाँ, अवसर और भारत की भूमिका

डॉ. अनूप मिश्र*

*प्रवक्ता, इंटरमीडिएट कॉलेज खामपार, देवरिया, उत्तर प्रदेश
Email id- anoopbhu8840@gmail.com
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.21212600
Accepted on: 30/06/2026 Published on: 06/07/2026

सारांश-

21वीं सदी का तीसरा दशक वैश्विक राजनीति में एक युगांतकारी परिवर्तन (Epochal Shift) का गवाह बन रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित पश्चिमी-केंद्रित और शीतयुद्ध के बाद की एकध्रुवीय (Unipolar) अमेरिकी व्यवस्था अब तेजी से एक जटिल बहुध्रुवीय (Multipolar) व्यवस्था में बदल रही है। प्रस्तुत शोध पत्र यथार्थवाद उदारवाद और सामाजिक रचनावाद (Social Constructivism) के सिद्धांतों के आलोक में समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करता है। यह लेख अमेरिका-चीन महाशक्ति प्रतिस्पर्धा, यूक्रेन और मध्य पूर्व (गाजा-लेबनान) संकट के कारण वैश्विक संस्थाओं (जैसे- संयुक्त राष्ट्र) की विफलता, और 'ग्लोबल साउथ' के उदय की पड़ताल करता है। इसके अतिरिक्त, यह शोध पत्र इस संक्रमण काल में भारत की 'गुटनिरपेक्षता' से 'बहु-संरेखण' की ओर बढ़ती रणनीतिक स्वायत्तता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है।

बीज शब्द- *बहुध्रुवीयता, वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल साउथ, रणनीतिक स्वायत्तता, भारत-प्रशांत, बहु-संरेखण।*

1. प्रस्तावना (Introduction)-

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (International Relations) का इतिहास निरंतर परिवर्तन, स्थापित व्यवस्थाओं के ढहने और उनके मलबे से नए ढाँचों के निर्माण की एक जटिल कहानी है। राज्य (States) किस प्रकार व्यवहार करते हैं, शक्तियाँ कैसे स्थानांतरित होती हैं, और वैश्विक शांति व संघर्ष के नियम कैसे तय होते हैं—ये सभी तत्व किसी भी दौर की 'वैश्विक व्यवस्था' (Global Order) को परिभाषित करते हैं। सन 1648 की वेस्टफेलिया की संधि (Treaty of Westphalia) ने आधुनिक संप्रभु राज्य प्रणाली (Sovereign State System) की नींव रखी थी। तब से लेकर आज तक, वैश्विक राजनीति ने कई करवटें ली हैं। 1815 की वियना कांग्रेस ने यूरोप में शक्ति संतुलन (Balance of Power) का एक बहुध्रुवीय मॉडल तैयार किया, जिसने लगभग एक सदी तक बड़े युद्धों को रोके रखा। हालाँकि, 20वीं सदी के दो विनाशकारी विश्व युद्धों ने इस

संतुलन को छिन्न-भिन्न कर दिया और दुनिया को एक नई व्यवस्था में धकेल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, वैश्विक राजनीति शीतयुद्ध (Cold War) के दौर में प्रवेश कर गई, जो एक स्पष्ट 'द्विध्रुवीय व्यवस्था' (Bipolar Order) थी। एक तरफ पूंजीवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा का नेतृत्व करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) था, तो दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाला सोवियत संघ (USSR)। इन दोनों महाशक्तियों के बीच का यह संघर्ष प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय छद्म युद्धों (Proxy Wars), हथियारों की होड़ और वैचारिक आधिपत्य के रूप में प्रकट हुआ।

वर्ष 1991 में सोवियत संघ का अचानक और अप्रत्याशित विघटन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में एक 'पैराडाइम शिफ्ट' (Paradigm Shift) लेकर आया। इस घटना ने द्विध्रुवीयता का अंत कर दिया और दुनिया में 'अमेरिकी एकध्रुवीयता' (Pax Americana / Unipolar Moment) की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक मोड़ पर प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने अपने प्रसिद्ध निबंध और पुस्तक "इतिहास का अंत" (The End of History and the Last Man) में यह घोषणा कर दी थी कि मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु आ चुका है, जहाँ पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र (Liberal Democracy) और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था (Free Market Capitalism) ने अंतिम विजय प्राप्त कर ली है। चार्ल्स क्रौथमर (Charles Krauthammer) जैसे विचारकों ने इसे "एकध्रुवीय क्षण" (The Unipolar Moment) कहा, जहाँ अमेरिका को चुनौती देने वाली कोई भी वैश्विक शक्ति शेष नहीं बची थी। हालाँकि, आज 21वीं सदी के तीसरे दशक (2026) के भू-राजनीतिक परिदृश्य में यह पश्चिमी-केंद्रित और एकध्रुवीय धारणा पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इतिहास का अंत नहीं हुआ, बल्कि इतिहास एक नई, अधिक जटिल और खतरनाक करवट के साथ लौट आया है। समकालीन वैश्विक राजनीति अब किसी एक महाशक्ति के इशारे पर या वाशिंगटन की इच्छा से संचालित नहीं होती। आज की वैश्विक व्यवस्था न तो पूरी तरह अमेरिकी प्रभुत्व को स्वीकार करती है और न ही पुरानी शीतयुद्धीय द्विध्रुवीयता में बंधी है। इसके विपरीत, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे राजनीतिक वैज्ञानिक 'संक्रमण काल' (Interregnum) या 'उत्तर-पश्चिमी बहुध्रुवीय विश्व' (Post-Western Multipolar World) कहते हैं।

इस नई व्यवस्था के उभार के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक हैं। सबसे प्रमुख कारक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) का एक आर्थिक, तकनीकी और सैन्य महाशक्ति के रूप में अभूतपूर्व उदय। चीन ने न केवल अमेरिकी आर्थिक आधिपत्य को चुनौती दी है, बल्कि 'बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) और अपनी वैश्विक सुरक्षा पहल (GSI) के माध्यम से एशिया-प्रशांत से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक एक समानांतर वैश्विक प्रभाव क्षेत्र तैयार कर लिया है। इसके साथ ही, रूसी संघ की आक्रामक पुनरुत्थानवादी (Revanchist) नीतियां, जिसने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के रूप में पश्चिमी सुरक्षा वास्तुकला को हिला कर रख दिया, यह दर्शाती हैं कि पुरानी महान शक्तियां (Great Powers) अपनी

भू-राजनीतिक सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, मध्य पूर्व (Middle East) में इजरायल, ईरान, सऊदी अरब और अन्य क्षेत्रीय अभिनेताओं के बीच बढ़ता संघर्ष, लाल सागर में नौवहन संकट, और एशिया-प्रशांत (Asia-Pacific) या हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में बढ़ता सैन्यीकरण यह संकेत देता है कि वैश्विक स्थिरता का पुराना ढांचा पंगु हो चुका है। इन सबके बीच, 'ग्लोबल साउथ' (Global South) का उदय—जिसमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं—एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। ये देश अब महाशक्तियों के किसी भी ब्लॉक में शामिल होने के बजाय अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) को प्राथमिकता दे रहे हैं और वैश्विक नियमों को तय करने में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं।

1.1 शोध के उद्देश्य (Research Objectives)

इस शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. समकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एकध्रुवीयता के पतन और बहुध्रुवीयता के उदय के कारणों की जांच करना।
2. प्रमुख वैचारिक सिद्धांतों (यथार्थवाद बनाम उदारवाद) के माध्यम से वर्तमान वैश्विक संघर्षों का विश्लेषण करना।
3. बहुपक्षीय संस्थाओं (UN, WTO, WHO) की प्रासंगिकता और उनके सामने मौजूद संकटों का मूल्यांकन करना।
4. समकालीन भू-राजनीति में 'ग्लोबल साउथ' के वैचारिक और रणनीतिक उभार को रेखांकित करना।
5. इस बदलती व्यवस्था में भारत की विदेश नीति के नए आयामों और रणनीतिक स्वायत्तता का विश्लेषण करना।

1.2 शोध का महत्व और प्रासंगिकता (Significance of the Study)- यह शोध कार्य समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के छात्रों, नीति निर्माताओं और रणनीतिक विश्लेषकों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अधिकांश मौजूदा साहित्य वैश्विक व्यवस्था को या तो केवल पश्चिमी दृष्टिकोण (Western-centric lens) से देखता है या फिर चीन-केंद्रित दृष्टिकोण से। यह शोध पत्र इन दोनों से इतर, 'ग्लोबल साउथ' और विशेष रूप से भारत के दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए एक संतुलित और बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह लेख केवल स्थापित सिद्धांतों को नहीं दोहराता, बल्कि 2026 के नवीनतम भू-राजनीतिक घटनाक्रमों (जैसे यूरेशियाई संकट, मध्य पूर्व संघर्ष और तकनीकी शीत युद्ध) को यथार्थवाद, उदारवाद और रचनावाद के सिद्धांतों के साथ जोड़कर एक व्यावहारिक और प्रामाणिक ढांचा प्रदान करता है।

2. सैद्धांतिक ढांचा (Theoretical Framework)- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए सिद्धांतों का सहारा लेना अनिवार्य है, क्योंकि ये सिद्धांत अराजक वैश्विक परिवेश (Anarchic International System) में राज्यों के व्यवहार को समझने का लेंस प्रदान करते हैं।

2.1 नव-यथार्थवाद (Neo-Realism) और थ्यूसीडाइड्स ट्रैप-केनेथ वॉल्ट्ज़ (Kenneth Waltz) के नव-यथार्थवाद के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना 'अराजक' (Anarchical) है, जिसका अर्थ है कि राज्यों के ऊपर कोई केंद्रीय वैश्विक सरकार नहीं है। इसलिए, प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है (Self-help system)। समकालीन दौर में ग्राहम एलिसन (Graham Allison) द्वारा प्रतिपादित "थ्यूसीडाइड्स ट्रैप" (Thucydides Trap) पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है। इसके अनुसार, जब एक उभरती हुई शक्ति (चीन) एक स्थापित महाशक्ति (अमेरिका) को चुनौती देती है, तो संरचनात्मक तनाव के कारण युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। अमेरिका और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर, ताइवान जलडमरूमध्य और प्रौद्योगिकी युद्ध (जैसे AI और सेमीकंडक्टर प्रतिबंध) इसी यथार्थवादी शक्ति-संघर्ष का परिणाम हैं।

2.2 नव-उदारवादी संस्थावाद (Neo-Liberal Institutionalism) का संकट- रॉबर्ट कोहेन (Robert Keohane) और जोसेफ नाई (Joseph Nye) जैसे विचारकों का तर्क था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (Institutions) और आर्थिक अंतर्निर्भरता (Economic Interdependence) राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं और युद्ध की संभावना को कम करते हैं। परंतु वर्तमान दशक में, "जटिल अंतर्निर्भरता" (Complex Interdependence) को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे "वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस" (Weaponization of Interdependence) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध, SWIFT बैंकिंग प्रणाली से रूस को बाहर करना, और चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (Rare Earth Elements) की आपूर्ति को रोकना यह दर्शाता है कि उदारवादी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अब सहयोग का साधन नहीं, बल्कि संघर्ष का अखाड़ा बन गई है।

2.3 सामाजिक रचनावाद (Social Constructivism) और पहचान की राजनीति- अलेक्जेंडर वेंड्ट (Alexander Wendt) के अनुसार, "अराजकता वैसी ही है जैसा राज्य उसे बनाते हैं" (Anarchy is what states make of it)। रचनावाद यह स्पष्ट करता है कि राज्यों का व्यवहार केवल भौतिक शक्ति से नहीं, बल्कि उनकी पहचान (Identity), संस्कृति और विचारों से तय होता है। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण केवल भू-राजनीतिक सुरक्षा (NATO विस्तार का विरोध) तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रूसी साम्राज्यवादी पहचान और ऐतिहासिक दावों से भी जुड़ा है। इसी प्रकार, वैश्विक राजनीति में 'पश्चिम बनाम शेष' (The West vs. The Rest) की धारणा वैचारिक और सांस्कृतिक पहचान के टकराव को दर्शाती है।

3. वैश्विक व्यवस्था का पुनर्गठन: प्रमुख चालक और प्रवृत्तियां-

3.1 अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा

21वीं सदी की भू-राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु वाशिंगटन और बीजिंग के बीच का 'शीत युद्ध 2.0' है। चीन की **'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI)** नीति ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में उसके आर्थिक प्रभाव का विस्तार किया है। दूसरी ओर, अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए **'इंडो-पैसिफिक' (Indo-Pacific)** रणनीति अपनाई है, जिसके तहत **QUAD** (अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया) और **AUKUS** (अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया) जैसे गठबंधनों को मजबूत किया गया है।

संकेतक	**संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)**	**चीन (PRC)**
रणनीतिक ध्यान	इंडो-पैसिफिक, नाटो, तकनीकी आधिपत्य	बेल्ट एंड रोड (BRI), वैश्विक सुरक्षा पहल (GSI)
आर्थिक रणनीति	डी-रिस्किंग (De-risking), मित्र-शरण (Friend-shoring)	दोहरी सुर्कलेशन (Dual Circulation), वि-डॉलरकरण
सैन्य उपस्थिति	वैश्विक सैन्य ठिकाने (Global Bases)	दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण, नौसैनिक विस्तार

3.2 यूरेशिया और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक फ्रैक्चर- यूक्रेन युद्ध ने यूरोपीय सुरक्षा वास्तुकला (European Security Architecture) को स्थायी रूप से बदल दिया है। इसने नाटो (NATO) को पुनर्जीवित किया है (फिनलैंड और स्वीडन का शामिल होना) और रूस को चीन तथा ईरान के अधिक करीब धकेल दिया है, जिससे एक नया 'निरंकुश अक्ष' (Axis of Autocracies) उभर रहा है। मध्य पूर्व में, अब्राहम समझौतों (Abraham Accords) के माध्यम से जो स्थिरता लाने का प्रयास किया गया था, वह 2023 के बाद भड़के इजरायल-हमास-हिजबुल्लाह संघर्ष के कारण पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। ईरान समर्थित 'प्रतिरोध के अक्ष' (Axis of Resistance) और इजरायल के बीच का यह संघर्ष वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्गों (जैसे लाल सागर संकट) के लिए गंभीर खतरा बन गया है।

4. बहुपक्षवाद का क्षरण और संस्थानों का संकट- वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सबसे चिंताजनक पहलू बहुपक्षीय संस्थानों (Multilateral Institutions) का पंगु होना है।

4.1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की विफलता- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज के भू-राजनीतिक यथार्थ को प्रतिबिंबित करने में पूरी तरह असमर्थ है। वीटो (Veto) पावर के दुरुपयोग ने इसे एक निष्क्रिय मंच बना दिया है। रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस द्वारा वीटो का प्रयोग और गाजा संकट पर अमेरिका द्वारा वीटो का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति बनाए रखने के अपने मूल अधिदेश (Mandate) में विफल रही है। भारत जैसे देशों द्वारा UNSC में सुधारों (Permanent Seat) की मांग को लगातार नजरअंदाज करना इसकी वैधता को और कम करता है।

4.2 नए वैकल्पिक मंचों का उदय (Minilateralism-पारंपरिक बहुपक्षवाद की विफलता ने 'लघुपक्षवाद' (Minilateralism) को जन्म दिया है। देश अब बड़े, अक्षम संगठनों के बजाय छोटे, परिणाम-उन्मुख समूहों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

1. BRICS+: हाल के वर्षों में ब्रिक्स का विस्तार (मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई का शामिल होना) यह दर्शाता है कि यह संगठन पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्व (विशेषकर G7) और डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने वाला एक प्रमुख मंच बन चुका है।

2. **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)**: यूरेशियाई सुरक्षा और स्थिरता के लिए चीन और रूस के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण मंच।

5. ग्लोबल साउथ का पुनरुत्थान (The Resurgence of the Global South)-

'ग्लोबल साउथ' शब्द अब केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली भू-राजनीतिक और आर्थिक ब्लॉक बन चुका है। विकासशील देश अब महाशक्तियों के संघर्ष में किसी एक का पक्ष लेने से इनकार कर रहे हैं।

5.1 रणनीतिक तटस्थता और सौदेबाजी की शक्ति- यूक्रेन युद्ध पर वैश्विक रुख ने यह स्पष्ट कर दिया कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के अधिकांश देशों ने पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस की सीधे तौर पर निंदा करने या उस पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। इन देशों की प्राथमिकताएं अलग हैं—खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ऋण संकट और जलवायु वित्त (Climate Finance)। ग्लोबल साउथ अब वैश्विक मंचों पर अपनी शर्तों पर सौदेबाजी (Bargaining) कर रहा है। भारत ने अपनी जी-20 (G20) अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ (African Union) को स्थायी सदस्यता दिलाकर खुद को ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज के रूप में स्थापित किया है।

6. समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की विदेश नीति- भारत की विदेश नीति इस समय अपने इतिहास के सबसे गतिशील चरण में है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के शब्दों में, भारत अब एक "संतुलनकारी शक्ति" (Balancing Power) से आगे बढ़कर एक "अग्रणी शक्ति" (Leading Power) बनने की ओर अग्रसर है।

6.1 गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) से बहु-संरेखण (Multi-Alignment)- शीतयुद्ध के दौर की पारंपरिक गुटनिरपेक्षता, जो कि निष्क्रिय या तटस्थ रहने की नीति थी, अब 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) और 'बहु-संरेखण' में बदल चुकी है। भारत अब किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग देशों के साथ संरेखित (Align) होता है।

1. भारत एक तरफ **QUAD** का हिस्सा बनकर अमेरिका के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है।

2. दूसरी तरफ, वह **BRICS** और **SCO** में रूस और चीन के साथ बैठता है, और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल का आयात जारी रखता है।

6.2 हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) में केंद्रीय भूमिका- भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का उद्देश्य इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी ढांचा तैयार करना है। भारत चीन की आक्रामक 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) नीति का मुकाबला करने के लिए क्षेत्र के देशों (जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया) के साथ रणनीतिक और रक्षा संबंधों को गहरा कर रहा है।

7. निष्कर्ष (Conclusion)-

21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अत्यंत अनिश्चित और खंडित (Fragmented) दौर से गुजर रहे हैं। उदारवादी वैश्विक व्यवस्था का ह्रास हो चुका है और एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था का जन्म हो रहा है, जो अभी पूरी तरह संस्थागत नहीं हुई है। इस संक्रमण काल (Interregnum) में महाशक्तियों के बीच टकराव, तकनीकी राष्ट्रवाद, और सुरक्षा गठबंधनों का पुनर्गठन जारी रहेगा। इस अराजक माहौल में, वैश्विक स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या महाशक्तियाँ प्रतिस्पर्धा के

साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, महामारी प्रबंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के नियमन जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग कर पाती हैं या नहीं। भारत के लिए, यह बहुध्रुवीय विश्व एक चुनौती भी है और अपनी रणनीतिक क्षमता, आर्थिक शक्ति और नैतिक नेतृत्व (ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में) के माध्यम से एक वैश्विक व्यवस्था-निर्माता (Rule-Maker) के रूप में उभरने का एक ऐतिहासिक अवसर भी है।

इस अराजक और खंडित विश्व व्यवस्था में भारत की विदेश नीति अपनी पारंपरिक रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकलकर एक 'अग्रणी शक्ति' (Leading Power) के रूप में खुद को स्थापित कर रही है। भारत ने शीतयुद्ध कालीन निष्क्रिय 'गुटनिरपेक्षता' (Non-Alignment) को व्यावहारिक 'बहु-संरेखण' (Multi-alignment) और 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) में बदल दिया है। भारत का यह दृष्टिकोण किसी अवसरवाद का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक यथार्थवादी नीति है जो राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखती है। भारत आज वैश्विक व्यवस्था में एक 'सेतु' (Bridging Power) की भूमिका निभा रहा है—वह एक तरफ पश्चिमी लोकतांत्रिक शक्तियों (QUAD, G7 के साथ जुड़ाव) का विश्वसनीय साझेदार है, तो दूसरी तरफ यूरेशियाई शक्तियों (BRICS और SCO में रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध) और ग्लोबल साउथ (G20 के माध्यम से अफ्रीकी संघ को शामिल कराना) की मुखर आवाज भी है।

8. संदर्भ –

- उपाध्याय, एस. (2021). 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति: चुनौतियाँ और रणनीतियाँ. ओरिएंट ब्लैकस्वान।
- कटारिया, आर. (2018). अंतर्राष्ट्रीय संबंध: सिद्धांत और समकालीन प्रवृत्तियाँ. रावत पब्लिकेशंस।
- खन्ना, वी. एन., और कुमार, एल. (2020). अंतर्राष्ट्रीय संबंध (5वां संस्करण). विकास पब्लिशिंग हाउस।
- दीक्षित, जे. एन. (2014). भारतीय विदेश नीति और उसके पड़ोसी. प्रभात प्रकाशन।
- पंत, पी. (2019). 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध (4था संस्करण). मैक्ग्रा हिल एजुकेशन इंडिया।
- मिश्रा, के. पी. (2016). गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और भारत का दृष्टिकोण. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति त्रैमासिक, 24(2), 115-128।
- शर्मा, एस. (2023). हिंद-प्रशांत क्षेत्र और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता. किताब महल।
- शुक्ला, वी. (2024). ब्रिक्स का विस्तार और वैश्विक राजनीति में ग्लोबल साउथ का उभार. विश्व राजनीति समीक्षा, 12(3), 45-62।
- सहाय, ए. (2022). अमेरिकी एकध्रुवीयता का अवसान और चीन का उभार. अनामिका पब्लिशर्स।
- सिंह, एन. के. (2025). बहुध्रुवीय विश्व में भारत: बहु-संरेखण की नई नीति. राजकमल प्रकाशन।
- Acharya, A. (2018). The end of American world order (2nd ed.). Polity Press.
- Allison, G. (2017). Destined for war: Can America and China escape Thucydides's trap? Houghton Mifflin Harcourt.
- Fukuyama, F. (1992). The end of history and the last man. Free Press.
- Ikenberry, G. J. (2020). A world safe for democracy: Liberal internationalism and the crises of global order. Yale University Press.

- Jaishankar, S. (2020). The India way: Strategies for an uncertain world. HarperCollins India.
- Jaishankar, S. (2024). Why Bharat matters. Rupa Publications India.
- Kaplan, R. D. (2012). The revenge of geography: What the map tells us about coming conflicts and the battle against fate. Random House.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). Power and interdependence (4th ed.). Longman.
- Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W. W. Norton & Company.
- Mearsheimer, J. J. (2018). The great delusion: Liberal dreams and international realities. Yale University Press.
- Mohan, C. R. (2022). India's geopolitical transmutation. Foreign Affairs, 101(4), 88-102.
- Narlikar, A. (2021). Holding up a mirror to the World Trade Organization: Leaders, laggards, and systemic crises. Global Governance, 27(2), 183-201.
- Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.
- Pant, H. V. (2021). India's foreign policy in a unipolar world. Routledge India.
- Stuenkel, O. (2016). Post-Western world: How emerging powers are remaking global order. Polity Press.
- Tharoor, S. (2012). Pax Indica: India and the world of the 21st century. Penguin Books India.
- Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. Addison-Wesley.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. International Organization, 46(2), 391-425.
- Zakaria, F. (2008). The post-American world. W. W. Norton & Company.